सामान्य कारण

बनाम

भारत संघ और अन्य

4 अप्रैल 2016

रिट याचिका (सिविल) संख्या: 114/2014

(जगदीश सिंह खेहर और सी. नागप्पन, जे. जे.)

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957-एस 8 , 4ए (4)-खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015- एस. 8ए-खनिज रियायत नियम, 1960-आरआर. 24ए, 24ए(6)(संशोधित के रूप में)-खनन पट्टाधारकों के लिए खनन कार्यों का निलंबन क्योंकि उनके पास मंजूरी/अनुमोदन/सहमति नहीं है, जो इस न्यायालय के आदेश से खनन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है-हालाँकि, जब भी मंजूरी/अनुमोदन/सहमति प्राप्त की जाती है, उक्त आदेश को संशोधित करने की अनुमति दी जाती है-आवेदन खनन कंपनियों द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कि क्या पट्टाधारकों को खनन ऑपरेशन जारी रखने का अधिकार है-अभिनिर्धारित जब तक राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है यह घोषणा करते हुए कि एक खनन पट्टा समाप्त हो गया है, खनन पट्टा को पट्टा दस्तावेज द्वारा प्रदान की गई पट्टा अवधि की समाप्ति की तारीख तक अस्तित्व में माना जाएगा। पट्टाधारक, उसे दिए बिना कम नहीं किया जा सकता है अवसर-उन स्थितियों में जहां एक आवेदन दायर किया गया है एक पट्टाधारक द्वारा, खनन संचालन एक के लिए नहीं किया गया था जब तक राज्य सरकार द्वारा इस तरह के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक

पट्टे की अवधि समाप्त नहीं मानी जाएगी-जहां कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, पट्टे को मूल पट्टे की अवधि से आगे बढ़ाया गया माना जाएगा। दो साल की और अवधि के लिए-पट्टाधारक के पास एक होगा मौजूदा खनन पट्टा, यदि मूल अनुदान की अवधि अभी भी 12.1.2015 पर मुद्रा में थी-पट्टाधारक जिसका मूल पट्टा है यदि मूल पट्टा का नवीनीकरण किया गया है, तो नवीनीकरण अवधि अभी भी 12.1.2015-पट्टाधारक पर मुद्रा में थी, जिसने इसके लिए आवेदन नहीं किया था, तब भी एक निर्वाह पट्टा होगा। मौजूदा पट्टा से कम से कम बारह महीने पहले खनन पट्टा का नवीनीकरण पट्टा समाप्त होने वाला था, असंशोधित के प्रावधानों के तहत एम. एम. डी. आर. अधिनियम और नियमों को वैध नहीं माना जाएगा। पट्टाधारक, पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद-पट्टाधारक जो नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है (मूल/प्रथम या बाद में नवीकरण), मौजूदा पट्टा देय होने से कम से कम बारह महीने पहले समाप्त होने के लिए, और यदि इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, तो यह नहीं होगा एक वैध/विद्यमान पट्टाधारक हो और आवेदन स्थानांतरित होने की स्थिति में पहले नवीनीकरण के लिए और उसे अस्वीकार नहीं किया गया है, इसे वैध/मौजूदा पट्टाधारक माना जाएगा जिसे जारी रखने का अधिकार होगा। खनन कार्य, 18.7.2014 के बाद दो साल की समाप्ति तक, अर्थात, 17.7.2016 तक-पट्टाधारक जिसने एक सेकंड (तीसरा या तीसरा) स्थानांतरित किया था बाद में नवीनीकरण आवेदन यू/एस। 8(3) अपरिवर्तित एम.एम.डी.आर. अधिनियम का, नवीनीकृत पट्टा देय होने से कम से कम बारह महीने पहले जिसकी अवधि समाप्त हो जाती है और जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है (हालांकि बिना संशोधन के किसी भी लाभ का हकदार नहीं है। एस.8 ए और संशोधित आर. 24 ए(6) 12.1.2015 तक, अभी भी का लाभ होगा एस. 8 ए(5) और (6) संशोधित एमएमडीआर अधिनियम।

सामान्य कारण बनाम भारत संघ (2014) 14 एससीसी

155:2014 (7) एस.सी.आर. 561-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2014 (7) एससीआर 561 संदर्भित किया गया पैरा 1

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः रिट याचिका (सिविल) सं. 114/2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

के साथ

डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 194/2014

ए. डी. एन. राव, सुश्री अपराजिता सिंह, श्री सिद्धार्थ चौधरी, न्यायमित्र।

नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंह, एएसजी, पी. चिदंबरम, डॉ. ए. एम. सिंघवी, गोपाल जैन, अशोक के. परिजा, दुष्यंत ए. दवे, निधेश गुप्ता, कृष्णन वेणुगोपाल, अरविंद पी. दातार, गोपाल सुब्रमण्यम, अशोक कुमार पांडा, ए. के. गांगुली, राकेश द्विवेदी, मानस रंजन, महापात्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, सुश्री नेहा राठी, निश्चल कुमार नीरज, समर सिंह कछवाहा, सुश्री मिनाक्षी ग्रोवर, नीरज कुमार शर्मा, विभु शंकर मिश्रा, सुधीर अग्रवाल, सुनील कुमार जैन, पवन श्री अग्रवाल, कौशिक चौधरी, जगमोहन शर्मा, के.पी.एस. चानी, अजय भार्गव, सुश्री वनिता भार्गव, जीवन बी. पांडा, कुबरत देव, रजत जरीवाल, आकाश बजाज, संजीव के. कपूर (मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए), गौरव केजरीवाल, केशव मोहन, सुजीत केशरी, सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री ताहिरा करंजावाला, सुश्री खुशबू बारी, सुश्री देविना सहगल, सुश्री नेहा खंडेलवाल, (मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी के लिए), नवीन कुमार, सुदीप डे, अर्नव दश, राजक कुमार मेहता, अभिषेक उपाध्याय, रमेंद्र मोहन पटनायक, धनञ्जय मिश्रा, आनंद

वी., अर्नव दश, सत्याब्रता पांडा, मनोरंजन पैकरे, तेजस्वी कुमार प्रधान, सुश्री संगीता मंडल, सुश्री स्वाति सिन्हा, अरिंदम गुहा, शांतनु बंसल, अरिजीत मजूमदार, (मेसर्स फॉक्स मंडल एंड कंपनी के लिए), श्रीमती कीर्ति रेनू मिश्रा, अनीश अग्रवाल, रमेश सिंह, शिव मंगल शर्मा, ललितेंदु महापात्रा, निशित अग्रवाल, (मेसर्स औरा एंड कंपनी के लिए), सुनील डोगरा, विवेक विश्नोई, अभिषेक शर्मा, सुचित मोहंती, अनुपम लाल दास, बालाजी श्रीनिवासन, ई. सी. अग्रवाल, हिमिंदर लाल, मुकुल कुमार, सत्येंद्र कुमार, तायेंजम मोमो सिंह, सुश्री रुचि कोहली, एस.एन. तेरदल, अधिवक्ता, उनके साथ उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय जगदीश सिंह खेहर, जे द्वारा दिया गया था

1. इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.5.2014 द्वारा कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ, (2014) 14 एससीसी 155, 102 खनन पट्टाधारकों को रोका किसी भी खनन कार्य को करने से। उपरोक्त आदेश पारित किया गया तथ्य यह है कि इनमें से किसी भी पट्टाधारक के पास कब्जा नहीं था खनन जारी रखने के लिए आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन/सहमति परिचालन. उपरोक्त आदेश दिनांक 16.5.2014 द्वारा स्वतन्त्रता प्रदान की गई जिन पट्टाधारकों का परिचालन निलंबित कर दिया गया था, उन्हें इसके बाद इस न्यायालय में जाना होगा इसके बाद अपेक्षित मंजूरी/अनुमोदन/सहमति प्राप्त करना संतुष्ट होने पर कोर्ट निलंबन आदेश रद्द कर देगा। हस्ताक्षर सत्यापित नहीं द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित -सतीश कुमार यादव दिनांक: 2016.04.04 15:15:45 टीएलटी

2. इस न्यायालय के समक्ष कई आवेदन दायर किये गये कारण: निलंबन के उपरोक्त आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें संबंधित आवेदकों ने दावा किया कि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है मंजूरी/अनुमोदन/सहमति, और इसके

अलावा, वे अब कानूनी रूप से थे खनन कार्य फिर से शुरू करने के पात्र। इस दौरान विचार हमारे हाथ में, श्री ए.डी.एन. राव, विद्वान न्याय मित्र बताया कि पट्टाधारकों को अनुमति देने का सवाल है खनन कार्यों को फिर से शुरू करने की बात तभी सामने आएगी, जब पट्टाधारक एक मौजूदा खनन पट्टा है. इसलिए यह प्रस्तुत किया गया था, कि पहले यह आवेदकों द्वारा उठाए गए दावे की वैधता का निर्धारण करता है कोर्ट को पहले यह जांच करनी चाहिए कि आवेदकों के पास जीवनयापन का साधन है या नहीं वैध पट्टे के तहत खनन कार्य जारी रखने का अधिकार।

3. यह प्रस्तुतिकरण विद्वान न्यायमित्र के हाथों आगे बढ़ा क्यूरिया का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा जोरदार विरोध किया गया आवेदक। उन्होंने हमारा ध्यान दिनांकित आदेश के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया 16.5.2014, कॉमन कॉज़ मामले में पारित किया गया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि यह न्यायालय ने ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं रखी थी, और इसलिए, विद्वान न्याय मित्र के हाथों अग्रिम समर्पण किया जाना चाहिए अस्वीकार किया जाए. उपर्युक्त अनुच्छेद 4, यहां नीचे दिया गया है:

> "4. हमने सीईसी की दिनांक 25.4.2014 की रिपोर्ट पर विचार किया है, और विभिन्न पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलें, और हमने पाया कि 102 खनन पट्टों में अपेक्षित शर्तें नहीं थीं वन (संरक्षण) के तहत पर्यावरणीय मंजूरी, अनुमोदन अधिनियम, 1980, अनुमोदित खनन योजना और/या संचालन की सहमति। इसकी सूची इन 102 खनन पट्टों को सीईसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है अनुलग्नक आर-2. हालाँकि, सीईसी ने रिपोर्ट में कहा है कि खनन इन 102 खनन पट्टों में परिचालन

निलंबित कर दिया गया है और ये 102 खनन पट्टों को अकार्यशील पट्टों की श्रेणी में रखा गया है। हम निर्देश दें कि सूचीबद्ध इन 102 खनन पट्टों में खनन कार्य किया जाए सीईसी की रिपोर्ट का अनुलग्नक आर-2 निलंबित रहेगा, लेकिन यह ऐसे पट्टेदारों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क करने का विकल्प खुला रहेगा पर्यावरणीय मंजूरी, वन (संरक्षण) के तहत मंजूरी अधिनियम, 1980, खनन योजना का अनुमोदन या संचालन की सहमति और जैसे जब खनन पट्टेदार सभी प्राप्त करने में सक्षम हों मंजूरी/अनुमोदन/सहमति के लिए वे इस न्यायालय में जा सकते हैं उनके मामलों के संबंध में इस अंतरिम आदेश में संशोधन।"

(हाइलाइटिंग - विद्वान परामर्श के अनुसार)

4. इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई स्थिति का अवलोकन करने के बाद 102 खनन पट्टों के संदर्भ में खनन कार्यों को निलंबित करना, यह है स्पष्ट है कि उक्त निर्देश एकमात्र विचार के लिए जारी किया गया था, कि सभी पर संबंधित पट्टाधारकों का कब्जा नहीं है मंजूरी/अनुमोदन/सहमति। और इस प्रकार, उन्हें इसकी अनुमति दी गई के आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें निलंबन, जब भी सभी मंजूरी/अनुमोदन/सहमति हो प्राप्त किया। हालाँकि, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि ऐसी मंजूरी, अनुमोदन और सहमति आवेदकों के लिए तभी सार्थक हो सकती है, जब वे मौजूदा खनन पट्टे के संदर्भ में हैं। मामले में एक पट्टाधारक उसके पास कोई मौजूदा खनन पट्टा नहीं है, उसे इसके तहत बाहर रखा गया है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधान, 1957 (इसके बाद इसे एमएमडीआर अधिनियम) के रूप में संदर्भित किया गया है, किसी को

भी आगे बढ़ाने से खनन कार्य. इसलिए, हम सबमिशन स्वीकार करते हैं श्री ए.डी.एन. राव द्वारा उन्नत और यह उपरोक्त कारण से भी है, कि हम इच्छुक खनन पट्टाधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील की आवश्यकता है क्या निलंबन आदेश दिनांक 16.5.2014 को हटाने के संबंध में पुष्टि की जानी है या नहीं, उनके पास मौजूदा खनन पट्टा था।

5. आरंभ करने के लिए, हमारा विचार था कि इस संबंध में निर्णय/निष्कर्ष वास्तविक दस्तावेज़ के रूप से सामने आएगा जिसके द्वारा खनन पट्टा प्रदान किया गया (या नवीनीकृत किया गया)। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि कटौती किस प्रकार की जाएगी क्या आवेदक-पट्टाधारकों के पास मौजूदा खनन था पट्टा(पट्टे), तथ्य और कानून का एक जटिल प्रश्न था। चूंकि वही है को रद्द करने के लिए आवेदकों के दावे से पहले हल किया जाना है निलंबन आदेश (- दिनांक 16.5.2014) स्वीकार किया जा सकता है, हम करेंगे ऐसे निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित करने का प्रयास करें।

6. एक पट्टाधारक के पास मौजूदा खनन पट्टा होगा, यदि अवधि मूल अनुदान मुद्रा में है। इसके अतिरिक्त, एक पट्टाधारक जिसका मूल पट्टा तब से समाप्त हो चुका है, यदि कोई मौजूदा पट्टा होगा मूल पट्टे का नवीनीकरण हो चुका है, नवीनीकरण की अवधि चालू है।

7. यह भी ध्यान देना जरूरी है कि शुरुआत में नवीनीकरण हो सकता है के तहत किसी भी खनन पट्टाधारक को कितनी भी बार प्रदान किया गया एमएमडीआर अधिनियम की असंशोधित धारा 8. मूल की अवधि अनुदान (खनन पट्टे का), साथ ही, नवीनीकरण की अवधि, और एक पट्टाधारक द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अनुमेय नवीनीकरणों की संख्या परिवर्तन आया. हम इसके तात्कालिक पहलू पर ध्यान केन्द्रित

करेंगे तात्कालिक क्रम में मामला, क्योंकि इसका मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, चाहे या नहीं, आवेदक-पट्टाधारकों के पास मौजूदा खनन का अधिकार है पट्टे. इसके लिए सबसे पहले इसका संदर्भ लिया जा सकता है खनन पट्टे के अनुदान के साथ-साथ नवीनीकरण को विनियमित करने का प्रावधान खनन पट्टा, अर्थात्, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8. तत्काल प्रावधान, जिस तरह से 1994 में संशोधन के बाद इसे संरचित किया गया था (जो स्थिति 18.7.2014 तक अपरिवर्तित रही), निकाली गई है यहाँ के अंतर्गत:

> "8. वह अवधि जिसके लिए खनन पट्टे दिए या नवीनीकृत किए जा सकते हैं।- (1) अधिकतम अवधि जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी:
>
> बशर्ते कि न्यूनतम अवधि जिसके लिए ऐसा कोई खनन पट्टा हो दी जा सकती है बीस वर्ष से कम नहीं;
>
> (2) एक खनन पट्टे को बीस साल से अधिक अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
>
> (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय है कि यह खनिज विकास के हित में है ऐसा करना आवश्यक है, यह दर्ज किए जाने वाले कारणों से अधिकृत हो सकता है निर्दिष्ट नहीं किए गए खनिजों के संबंध में खनन पट्टे का नवीनीकरण आगे की अवधि या अवधियों के लिए पहली अनुसूची के भाग-ए और भाग-बी प्रत्येक मामले में बीस वर्ष से अधिक नहीं।

(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (3) में निर्दिष्ट खनिज के संबंध में कोई खनन पट्टा नहीं दिया गया है प्रथम अनुसूची के भाग-ए या भाग-बी को छोड़कर नवीनीकृत किया जाएगा केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी।"

(जोर हमारा है)

धारा 8(1) के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकतम जिस अवधि के लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है, वह तीस साल से अधिक नहीं होगी। मूल अनुदान की समाप्ति के बाद खनन पट्टा हो सकता है पहली बार में बीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, धारा 8(2) के अंतर्गत। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, नवीनीकरण धारा 8(2) के तहत विचार किया गया, इसे "पहला" कहा जाएगा नवीनीकरण" "पहले नवीनीकरण" के लिए राज्य की मंजूरी की आवश्यकता थी सरकार, और केंद्र सरकार की मंजूरी. आगे नवीनीकरण, धारा 8(2) के तहत दिए गए पहले नवीनीकरण की समाप्ति के बाद, भी अनुमति योग्य थे, और धारा 8(3) के तहत प्रदान किए गए थे एमएमडीआर अधिनियम. सभी उद्देश्यों के लिए धारा 8(3) के तहत नवीनीकरण (ओं) को निर्धारित किया गया है और उद्देश्यों को इसके बाद "दूसरा (या तीसरा, या)" के रूप में वर्णित किया जाएगा चौथा) नवीनीकरण"। धारा 8(3) के तहत नवीनीकरण प्रदान किया जा सकता है केवल यदि राज्य सरकार अपनी संतुष्टि व्यक्त करती है, तो अनुदान दिया जाएगा दूसरा या बाद का नवीनीकरण, खनिज के हित में होगा विकास। इसके अलावा, "दूसरा नवीनीकरण" या उससे भी आगे नवीनीकरण के लिए भी केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यद्यपि बाद के नवीनीकरण की अवधि का कोई महत्व नहीं है, जहां तक वर्तमान विवाद का सवाल है, इसका उल्लेख किया जा

सकता है, दूसरे, तीसरे या आगे सहित सभी बाद के नवीनीकरण नवीनीकरण, व्यक्तिगत रूप से बीस साल से अधिक की अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

8. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 पर हमारे द्वारा दी गई व्याख्या (जैसा कि यह 1994 में अस्तित्व में था), खनिज के नियम 24 ए से समर्थन पाता है मिनरल कन्सेशन नियम, 1960 (इसके बाद खनिज रियायत नियम के रूप में संदर्भित)) - जैसा कि नियम 18.7.2014 से पहले मौजूद था। नियम 24 ए में फिर इसे जिस प्रकार से संरचित किया गया, वह नीचे दिया गया है:

> "24 ए. खनन पट्टे का नवीनीकरण. –(1) नवीनीकरण के लिए एक आवेदन खनन पट्टा राज्य सरकार को फॉर्म जे में दिया जाएगा उस तारीख से कम से कम बारह महीने पहले जिस दिन पट्टा देय है राज्य सरकार जैसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से समाप्त हो सकती है इस संबंध में निर्दिष्ट करें.
>
> (2) किसी के संबंध में दिए गए खनन पट्टे का नवीनीकरण या नवीनीकरण अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ए और भाग बी में निर्दिष्ट खनिज राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन से प्रदान किया जा सकता है
>
> (3) किसी के संबंध में दिए गए खनन पट्टे का नवीनीकरण या नवीनीकरण खनिज प्रथम अनुसूची के भाग ए और भाग बी में निर्दिष्ट नहीं है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की अनुमति दी जा सकती है:

बशर्ते कि दूसरे या बाद के लिए मंजूरी देने से पहले खनन पट्टे के नवीनीकरण के मामले में राज्य सरकार रिपोर्ट मांगेगी महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो से, कि क्या यह नवीनीकरण प्रदान करना खनिज विकास के हित में होगा खनन पट्टे का.

बशर्ते कि यदि नियंत्रक से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है सामान्य, भारतीय खान ब्यूरो प्राप्ति के तीन महीने की अवधि में राज्य सरकार से संचार के, यह माना जाएगा भारतीय खान ब्यूरो के पास देने के लिए कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है खनन पट्टा नवीनीकरण स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

(4) खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन का निपटारा किया जाएगा इसकी प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर।

(5) यदि किसी आवेदन का निस्तारण निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है उपनियम (4) के तहत यह माना जाएगा कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

(6) यदि खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन समय के भीतर किया जाता है उपनियम (1) में उल्लिखित प्रकरणों का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है पट्टे की समाप्ति तिथि से पहले उस पट्टे की अवधि होगी राज्य तक एक और अवधि के लिए बढ़ाया गया माना जाता है सरकार उस पर आदेश पारित करती है.

xxx xxx xxx"

(जोर हमारा है)

नियम 24 ए के उप-नियम (1) के अवलोकन से पता चलता है कि एक आवेदन के लिए खनन पट्टे का नवीनीकरण, मौजूदा खनन पट्टे की समाप्ति की तारीख के कम से कम बारह महीने पहले किया जाना था. इसलिए यह आवश्यक है हमें रिकॉर्ड करने के लिए, जब तक कि ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया हो मौजूदा खनन पट्टे की समाप्ति की तारीख से बारह महीने पहले खनिज रियायत नियमावली के नियम 24 ए के अनुसार ऐसा नहीं हो सका मनोरंजन किया. और यह भी कि, द्वारा धारित खनन पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टाधारक का अस्तित्व समाप्त माना जाएगा पट्टा दस्तावेज़ में दर्शाई गई अवधि, यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं था प्राथमिकता दी गई है.

9. अगला प्रासंगिक प्रावधान नियम 24 ए का उप-नियम (4) है खनिज रियायत नियम. तत्काल उप-नियम की आवश्यकता है, कि एक नवीनीकरण के लिए आवेदन का निस्तारण छह माह के भीतर किया जाएगा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख. हमने यहां ऊपर निकाला है, नियम 24 ए का उप-नियम (5), जिसमें यह अनिवार्य था कि एक आवेदन नवीनीकरण के लिए, जिसका छह की अवधि के भीतर निस्तारण नहीं किया गया था महीने, जैसा कि खनिज रियायत के नियम 24 ए(4) के तहत प्रदान किया गया है नियमों को अस्वीकार कर दिया गया माना जाएगा। हालाँकि यह प्रासंगिक है ध्यान दें, कि उपरोक्त उप-नियम (5) को एक द्वारा छोड़ दिया गया है संशोधन, 7.1.1993 से प्रभावी। इसे रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है उप-नियम (6) को एक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो प्रभावी है 27.9.1994. खनिज रियायत नियमावली के नियम 24 ए का उपनियम (6) है दृढ़ संकल्प के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे आवेदक-पट्टाधारक के पास मौजूदा खनन पट्टा है क्योंकि a बड़ी संख्या में आवेदक

अपने समर्थन में तत्काल नियम पर भरोसा करते हैं मौजूदा खनन पट्टे पर कब्ज़ा होने का दावा। उपनियम (6) उपरोक्त अभिधारणा यह है कि यदि किसी खनन के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है पट्टा (मौजूदा तारीख से पहले, बारह महीने के भीतर बनाया गया)। पट्टा समाप्त होना था), सक्षम द्वारा निपटान नहीं किया गया था प्राधिकरण, पट्टे की अवधि को बढ़ाया हुआ माना जाएगा राज्य सरकार द्वारा निपटान आदेश पारित करने तक की एक और अवधि नवीनीकरण आवेदन. इसलिए, खनन जारी रखने का अधिकार है ऐसा प्रतीत होता है कि साधारण कारण से संचालन अनंत काल तक जारी रहेगा राज्य सरकार, जो सक्षम प्राधिकारी थी, ने ऐसा नहीं किया नवीनीकरण की मांग करने वाले अधिकांश लंबित आवेदनों पर कोई आदेश पारित किया।

10. वैधानिक शासन से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना एमएमडीआर अधिनियम के तहत खनन पट्टों की संख्या, और खनिज रियायत नियम, 21.4.2014 को हुए, जब इस न्यायालय ने गोवा में एक आदेश पारित किया फाउंडेशन बनाम भारत संघ, (2014) 6 एससीसी 590, और निम्नानुसार आयोजित किया गया:

> “27. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1), जो प्रदान करती है अधिकतम और न्यूनतम अवधि जिसके लिए खनन पट्टा हो सकता है दी गई मंजूरी गोवा में डीम्ड खनन पट्टों पर लागू नहीं होगी क्योंकि उन्मूलन अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि ऐसे मानित खनन पट्टों की अवधि छह महीने तक बढ़ जाएगी एमएमडीआर अधिनियम. में किसी भी बात के बावजूद सहमति की तारीख दूसरे शब्दों में, इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1), एक

डीम्ड की अवधि गोवा में खनन पट्टा 22.11.1987 (छह महीने) को समाप्त होना था सहमति की तिथि) एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत, ए खनन पट्टे को अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। धारा 8 की उप-धारा (3), हालांकि, यह प्रदान करती है उप-धारा (2) में निहित कुछ भी, यदि राज्य सरकार का है राय है कि खनिज विकास के हित में यह आवश्यक है ऐसा करने के लिए, यह दर्ज किए जाने वाले कारणों से, के नवीनीकरण को अधिकृत कर सकता है भाग ए और भाग बी में निर्दिष्ट नहीं किए गए खनिजों के संबंध में खनन पट्टा पहली अनुसूची की एक अतिरिक्त अवधि या अवधि से अधिक नहीं प्रत्येक मामले में बीस वर्ष. इस प्रकार, पहले नवीनीकरण से परे नवीनीकरण राज्य सरकार पर बीस वर्ष की अवधि सशर्त है यह राय बनाई जा रही है कि यह खनिज विकास के हित में है ऐसा करना आवश्यक है और राज्य सरकार पर भी सशर्त है लोहे के संबंध में खनन पट्टे के ऐसे नवीनीकरण के कारणों को दर्ज करना अयस्क जो प्रथम अनुसूची के भाग ए और भाग बी में निर्दिष्ट नहीं है। टिस्को लिमिटेड बनाम भारत संघ (1996) 9 एससीसी 709 में, इस न्यायालय ने कहा है कि धारा 8 की उपधारा (3) की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि आम तौर पर निर्दिष्ट समय से परे पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए उपधारा (2) और केवल तभी जब सरकार का विचार हो कि वह ऐसा करेगी खनिज विकास के हित में हो, नवीनीकरण का अधिकार है उचित कारण दर्ज करने के बाद किसी पट्टेदार को आगे की अवधि के लिए पट्टे पर देना ऐसा करने से। इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में आगे कहा है

कि यह उपाय को विधायी योजना में शामिल किया गया है मनमानी के विरुद्ध और कानून की मूल भावना की रक्षा करना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

28. एमसी नियम एमएमडीआर अधिनियम की धारा 13 के तहत बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा और जाहिर तौर पर नहीं बनाया जा सका अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत तरीके से। उपनियम (6) एमसी नियमों के नियम 24 ए में प्रावधान है कि:

“24-ए.(6) यदि किसी खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर निस्तारण नहीं किया जाता है राज्य शासन द्वारा पट्टा समाप्ति की तिथि से पूर्व की अवधि उस पट्टे को आगे बढ़ाया हुआ माना जाएगा राज्य सरकार द्वारा उस पर आदेश पारित करने तक की अवधि।" यह उपनियम उपधारा (3) के तहत नवीनीकरण पर लागू नहीं हो सकता एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 क्योंकि इस प्रावधान के तहत नवीनीकरण राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश के बिना नहीं बनाया जा सकता खनिज विकास के हित में नवीनीकरण के कारणों को दर्ज करना। दूसरे शब्दों में, जब तक पट्टेदार के पास नवीनीकरण का अधिकार है जो खनन पट्टे के मामले में अधिकतम बीस वर्ष अवधि के लिए है, किसी पट्टे के मानित विस्तार से संबंधित प्रावधान हो सकता है संचालित करें, लेकिन यदि खनन पट्टे के नवीनीकरण का अधिकार निर्भर है राज्य सरकार यह राय बना रही है कि यह हित में है खनिज विकास ऐसा करना राज्य के लिए आवश्यक है सरकार ने

इसके कारणों को दर्ज करते हुए डीम्ड के संबंध में एक प्रावधान किया है राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित होने तक विस्तार नवीनीकरण का आवेदन लागू नहीं हो सकता। इसलिए, हम इस राय के हैं एमसी नियमों के नियम 24 ए का उपनियम (6) किस मामले में लागू होगा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत पहला नवीनीकरण अन्य एमसी नियमों के नियम 24 ए के उप-नियम (9) के तहत आने वाला मामला, लेकिन धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा एमएमडीआर अधिनियम. हमारे विचार में, पट्टेदारों के खनन पट्टों को माना जाता है की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत 22.11.1987 को गोवा समाप्त हो गया। उन्मूलन अधिनियम एवं नवीनीकरण की अधिकतम अवधि 20 वर्ष जैसा कि उप-धारा (2) में प्रदान किया गया है, गोवा में खनन पट्टे माने गए हैं एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 नियम 24 ए के उप-नियम (8) और (9) के साथ पढ़ें एमसी नियम 22.11.2007 को समाप्त हो गए।

(जोर हमारा है)

11. इस समय, यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि इससे पहले गोवा फाउंडेशन मामले में राज्य सरकार का फैसला नियम 24 ए के उप-नियम (6) की व्याख्या करते हुए पट्टाधारकों को इसकी अनुमति दी गई है बिना किसी बाहरी सीमा के खनन कार्य जारी रखें। इस दृष्टिकोण से गोवा फाउंडेशन मामले में जो निष्कर्ष निकाला गया, वह सही निकला यह समझा गया कि इस तरह के ऑपरेशन (नियम के दायरे में) जारी रह सकते हैं 24 ए(6), जिसके तहत ऐसा आवेदन किया गया था) की समाप्ति तक प्रथम

नवीनीकरण के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि, अर्थात, की अवधि के लिए बीस साल। दूसरे और बाद के नवीनीकरण को नहीं माना गया स्वचालित। क्योंकि दूसरे और बाद के नवीनीकरण के लिए इसकी आवश्यकता होती है दर्ज कारणों के माध्यम से राज्य सरकार की संतुष्टि, जैसे यहाँ ऊपर देखा गया। इसलिए, गोवा फाउंडेशन में फैसले के बाद मामले में, यह समझ में आया कि स्पष्ट आदेश के अभाव में दूसरे या बाद के नवीनीकरण के बाद खनन पट्टा समाप्त हो जाएगा प्रथम नवीनीकरण की अवधि पूर्ण होना।

12. इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को प्रभावी बनाने के लिए गोवा फाउंडेशन मामले में, नियम 24ए(6) में संशोधन किया गया 18.7.2014. उपरोक्त संशोधन नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "नियम 24-ए
>
> xxx xxx xxx
>
> (6) यदि किसी खनन पट्टे के प्रथम नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय का निपटान राज्य द्वारा नहीं किया जाता है पट्टे की समाप्ति तिथि से पूर्व शासन, उसकी अवधि लीज को दो वर्ष अवधि की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया हुआ माना जाएगा वर्ष या जब तक राज्य सरकार उस पर आदेश पारित नहीं करती, जो भी हो पहले:
>
> बशर्ते कि जिन पट्टों में खनन के पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन हों राज्य सरकार को किसे पट्टे दिये गये हैं और किन्हें नहीं दिये गये हैं की समाप्ति तिथि से पूर्व राज्य शासन द्वारा निस्तारण कर दिया

गया है पट्टे पर हैं और अधिसूचना की तारीख तक निपटान के लिए लंबित हैं इस संशोधन को आगे बढ़ाया हुआ माना जाएगा इसके लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि संशोधन या जब तक राज्य सरकार उस पर आदेश पारित नहीं करती प्रथम नवीनीकरण के लिए अनुमत अधिकतम अवधि की समाप्ति की तारीख, जो भी जल्द से जल्द हो:

बशर्ते कि इस उप-नियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे खान एवं खनिज की धारा 8 की उपधारा (3) के अंतर्गत नवीनीकरण (विकास औरविनियमन) अधिनियम, 1957"

(जोर हमारा है)

उपरोक्त संशोधन को ध्यानपूर्वक समझना होगा। निस्संदेह, खनिज रियायत नियमावली के नियम 24 ए के उपनियम (6) में संशोधन अब प्रावधान है कि खनन कार्य की अवधि मानी जाएगी की समाप्ति के बाद अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया मूल अनुदान की अवधि, जब तक कि निश्चित रूप से, राज्य सरकार नहीं लेती नवीनीकरण हेतु आवेदन पर सोच-समझकर लिया गया निर्णय। हम इस विचार के हैं, कि तत्काल प्रावधान को, की निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए पूर्ववर्ती/पिछला नियम 24 ए (जो तत्काल संशोधन तक अस्तित्व में था 18.7.2014 को लागू हुआ)। असंशोधित प्रावधान, एक अभिधारणा निर्धारक आदेश के अभाव में खनन पट्टे की असीमित अवधि, नवीनीकरण के लिए आवेदन पर. इसलिए, भले ही मूल पट्टा था कई वर्ष पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन यदि नवीनीकरण आवेदन को प्राथमिकता दी गई हो नियम 24 ए(1) के तहत निर्धारित अनुमेय समय के भीतर तत्काल संशोधन प्रभावी होने तक यह जारी रहेगा 18.7.2014 को. इस निष्कर्ष का

महत्व इसलिये है, कि नए नियम 24ए(6) का प्रावधान- 18.7.2014 को जानबूझकर संशोधित किया गया बशर्ते, वह पट्टा अवधि जहां मांग के लिए आवेदन दायर किए गए थे "प्रथम नवीनीकरण" को आगे के लिए बढ़ा हुआ माना जाएगा संशोधन के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि उपनियम (6). तदनुसार, उन सभी मामलों में जहां "पहला नवीनीकरण" हुआ था मांग की गई, लेकिन निर्धारित नहीं होने पर, खनन कार्य बढ़ा दिए गए, विधि सम्मत कार्यवाही द्वारा दिनांक 18.07.2014 तक

13. इस न्यायालय के समक्ष अधिकांश आवेदकों का मामला यह है कि वे नियम 24ए(1) के तहत अनुमत समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया था, और इस प्रकार, नियम 24ए के असंशोधित उप-नियम (6) के कारण, और इसके बाद नियम 24 ए के संशोधित उपनियम (6) के आधार पर उनका खनन कार्य जारी रखने का अधिकार माना जाएगा 18.7.2016 तक बढ़ाया गया। हम पाते हैं कि उनका दावा वैध है, और स्वीकार करते हैं वही, जहां तक कानूनी स्थिति का सवाल है, लेकिन केवल साथ "प्रथम नवीनीकरण" का संदर्भ। हम यह समझाने में जल्दबाज़ी कर सकते हैं, कि तुरंत असंशोधित और की व्याख्या से दृढ़ संकल्प उभरता है संशोधित नियम 24ए(6)। क्या बाद के संशोधनों से परिवर्तन होगा स्थिति, इसके बाद निर्धारित की जा रही है।

14. इस स्तर पर एक स्पष्टीकरण अत्यावश्यक है। के गुजर जाने के बाद गोवा फाउंडेशन मामले में 21.4.2014 को आदेश, "पहले" को कायम रखते हुए नियम 24ए के तहत नवीनीकरण, आगे के पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा बीस वर्ष की अवधि, अधीन विचारित अवधि की समाप्ति के बाद मूल अनुदान, या जैसा कि ऊपर व्याख्या की गई है। कोई समान नहीं था गोवा फाउंडेशन मामले के बाद, "दूसरे नवीनीकरण" का स्वचालित अनुदान। इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, निष्कर्ष दर्ज किया गया यहाँ ऊपर, केवल के संदर्भ में प्रासंगिक माना जाना चाहिए "प्रथम नवीनीकरण" का

अनुदान। यह दोहराना जरूरी है कि गोवा में फाउंडेशन मामले में, इस न्यायालय ने माना था कि दूसरा नवीनीकरण होगा राज्य सरकार द्वारा कारण दर्ज करते हुए पारित आदेश के अधीन ऐसा करना खनिज विकास के हित में था। की जरूरत नहीं उल्लेख करें, कि दूसरे या बाद के नवीनीकरण की भी आवश्यकता है केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी - जैसा कि नीचे दिया गया है एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8(4)। नियम 24ए में संशोधन किया गया 18.7.2014, विशेष रूप से, उप-नियम (6) का दूसरा परंतुक, छोड़ देता है किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं है, कि स्वचालित विस्तार के साथ पोस्ट किया गया पहले नवीनीकरण का संदर्भ, दूसरे पर लागू नहीं होगा या बाद के नवीनीकरण. इसलिए आगे यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है दूसरे और बाद के नवीनीकरण के मामलों में, संशोधित नियम 24ए(6) लीज अवधि को दो साल की अगली अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा संशोधन की तिथि. इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, में एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8(3) के तहत मांगे गए नवीनीकरण के संबंध में (साथ पढ़ें) खनिज रियायत नियमों के नियम 24ए(6) - 18.7.2014 को संशोधित), सभी दूसरे नवीनीकरण जिन्हें राज्य द्वारा समर्थित माना गया था फैसले की तारीख से सरकारें समाप्त हो जाएंगी गोवा फाउंडेशन मामला, यानी, 21.4.2014, और स्पष्ट रूप से, से प्रभाव से 18.7.2014, जब नियम 24ए(6) का दूसरा प्रावधान तदनुसार प्रदान किया गया। बेशक, जब तक सरकार ने स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया था लेखन, जैसा कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8(3) के तहत अनिवार्य है, का विस्तार किया गया है दूसरे या बाद के नवीनीकरण द्वारा मौजूदा खनन पट्टा।

15. 16.5.2014 को, इस न्यायालय ने (सामान्य कारण मामले में) पारित किया एक आदेश जिसमें राज्य सरकार को लंबित मामलों का निपटान करने की आवश्यकता

है छह महीने के भीतर दूसरे और बाद के नवीनीकरण के लिए आवेदन। उपरोक्त आदेश का ऑपरेटिव भाग नीचे निकाला जा रहा है:

> "10. साथ ही सीईसी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियाँ, हम एक अंतरिम उपाय के रूप में निर्देशित करते हैं ये 26 पट्टे दूसरे और बाद के नवीनीकरण के रूप में चल रहे हैं राज्य द्वारा पारित नवीनीकरण के किसी स्पष्ट आदेश के बिना राज्य सरकार को सरकार चलाने की इजाजत नहीं दी जायेगी जब तक खदानों की धारा 8(3) के संदर्भ में स्पष्ट आदेश पारित नहीं हो जाते और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और हम भी निर्देश दें कि सभी नवीनीकरण आवेदन खानों की धारा 8(3) के तहत हों। और खनिज (विकास एवंविनियमन) अधिनियम, 1957 होगा राज्य सरकार द्वारा छह के भीतर विचार कर निस्तारण किया गया आज से महीनों बाद. हम आगे निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार ऐसा करेगी पहले पट्टों के संबंध में नवीनीकरण आवेदनों पर विचार करें जो थे लौह या मैंगनीज अयस्क को कच्चे रूप में उपलब्ध कराने के लिए कैप्टिव खनन की अनुमति दी गई उद्योगों के लिए सामग्री और उसके बाद ही नवीनीकरण पर विचार करें अन्य पट्टों के संबंध में आवेदन। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विचार-विमर्श की पूरी प्रक्रिया और अधिनियम की धारा 8(3) के अंतर्गत नवीनीकरण आवेदनों का निपटान किया जाता है आज से छह महीने के भीतर पूरा हो गया। उपरोक्त अंतरिम के साथ निर्देश, अंतरिम मामले का निपटारा किया जाता है।"

(जोर हमारा है)

ऐसा लगता है, कि राज्य के रूप में उपरोक्त निर्देश का उल्लंघन किया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारों के पास इसका अनुपालन करने की कोई सुविधा या क्षमता नहीं थी। परिणामस्वरूप, 2014 के आईए संख्या 21 में एक और आदेश पारित किया गया, जो समय विस्तार के लिए दायर किया गया था। का अतिरिक्त समय देने का आदेश तीन महीने, दिनांक 16.5.2014, यहां नीचे निकाले गए हैं:

"आई.ए. स., 21/2014

श्री एल. नागेश्वर राव को सुनने के बाद, वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए उड़ीसा राज्य के लिए, हम उन्हें एक और अनुदान देना उचित समझते हैं तीन महीने" दिनांकित आदेश का अनुपालन करने हेतु आज से समय 16.05.2014.

हम सभी निजी उत्तरदाताओं को आदेशों पर आपत्ति करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं जिसका अनुपालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा पारित किया जा सकता है न्यायालय का आदेश दिनांक 16.05.2014.

आई.ए. स., 21/2014 का तदनुसार निपटान किया जाता है।"

(जोर हमारा है)

16. संसद राज्य की दुर्दशा के प्रति सचेत थी सरकारें. यह भी महसूस किया गया कि खनन पट्टे देने की व्यवस्था और उनके नवीनीकरण में एकरूपता लाकर बदलाव की जरूरत है प्रक्रिया। इसलिए, धारा 8A में संशोधन किया गया। तात्कालिक

12.1.2015 से एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन डाला गया। उपरोक्त संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत धारा 8ए निकाला जा रहा है यहाँ के अंतर्गत:

> "8ए. कोयले के अलावा अन्य खनिजों के लिए खनन पट्टा देने की अवधि, लिग्नाइट और परमाणु खनिज- (1) इस धारा के प्रावधान होंगे के भाग ए और भाग बी में निर्दिष्ट खनिजों के अलावा अन्य खनिजों पर लागू होता है पहली अनुसूची.
>
> (2) खदानों के प्रारंभ होने की तारीख से और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015, सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की अवधि के लिए दिए जाएंगे।
>
> (3) खदान शुरू होने से पहले दिए गए सभी खनन पट्टे और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 पचास वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया माना जाएगा।
>
> (4) पट्टा अवधि की समाप्ति पर, पट्टा प्रस्तुत किया जाएगा इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी।
>
> (5) उपधारा (2), (3) और में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (4), तारीख से पहले दिए गए पट्टे की अवधि खान एवं खनिज (विकास एवं) का प्रारंभ विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015, जहां खनिज का उपयोग बंदी के लिए किया जाता है उद्देश्य, बढ़ाया जाएगा और बढ़ा हुआ समझा जाएगा की तिथि से 31 मार्च, 2030 को समाप्त होने वाली अवधि तक अंतिम बार नवीनीकरण की अवधि की समाप्ति या पूरा होने तक नवीनीकरण अवधि, यदि कोई हो, या अनुदान की

तारीख से पचास वर्ष की अवधि ऐसे पट्टे पर, जो भी बाद में हो, इस शर्त के अधीन है कि सभी पट्टे के नियम एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(6) उपधारा (2), (3) और में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (4), तारीख से पहले दिए गए पट्टे की अवधि खान एवं खनिज (विकास एवं) का प्रारंभ विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015, जहां खनिज का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है कैप्टिव उद्देश्य की तुलना में, बढ़ाया जाएगा और माना जाएगा 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि तक बढ़ा दिया गया अंतिम बार नवीनीकरण की अवधि की समाप्ति की तारीख से या तक नवीनीकरण अवधि, यदि कोई हो, या उससे पचास वर्ष की अवधि पूरी करना शर्त के अधीन ऐसे पट्टे के अनुदान की तारीख, जो भी बाद में हो कि पट्टे की सभी नियम एवं शर्तों का पालन किया गया है।

(7) दिए गए पट्टे का कोई भी धारक, जहां खनिज का उपयोग बंदी के लिए किया जाता है उद्देश्य, आयोजित नीलामी के समय पहले इनकार का अधिकार होगा पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे पट्टे के लिए।

(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, की अवधि खनन पट्टे, जिसमें सरकार के मौजूदा खनन पट्टे भी शामिल हैं कंपनियाँ या निगम ऐसे होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है केंद्र सरकार।

(9) इस धारा के प्रावधान, किसी भी बात के होते हुए भी उसमें, तारीख से पहले दिए गए खनन पट्टे पर लागू नहीं होगा खान एवं

खनिज (विकास एवं) का प्रारंभ विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015, जिसका नवीनीकरण किया गया है अस्वीकार कर दिया गया है, या जो निर्धारित किया गया है, या व्यपगत हो गया है।"

17. संशोधित एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8A(2) के संदर्भ में, सभी भविष्य खनन अनुदान, पचास वर्षों की एक समान अवधि के लिए होगा। धारा 8ए(3) परिकल्पना की गई है, कि सभी मूल खनन पट्टा अनुदान, से पहले दिए गए धारा 8ए का सम्मिलन, एमएमडीआर अधिनियम में (12.1.2015 से प्रभावी) यह भी पचास वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया माना जाएगा।

18. धारा 8ए(5) बंदी के लिए दिए गए खनन पट्टों से संबंधित है उद्देश्य, और मुख्य रूप से एक के तहत काम कर रहे पट्टाधारकों के लिए लक्षित है नवीकरण. धारा 8ए(5) तीन अलग-अलग आकस्मिकताओं का अनुमान लगाता है।

सबसे पहले, 12.1.2015 से पहले दिए गए सभी खनन पट्टों की अवधि "...होगी बढ़ाया जाएगा और बढ़ा हुआ माना जाएगा..." 31.3.2030 तक, "...पिछले नवीनीकरण की अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी बनाया..."। यह स्पष्ट है कि "विस्तार" का प्रश्न उठेगा आम तौर पर "समाप्ति" के बाद ही उत्पन्न होता है। चूंकि दोनों शब्द - "विस्तार" और "एक्सपायरी" को उपधारा (5) में जगह मिलती है, हमारा मानना है कि धारा 8ए(5) नवीनीकरण की समाप्ति के बाद भी आकर्षित होता है। तात्कालिक "नवीनीकरण की समाप्ति अंतिम" शब्दों के प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है बनाया", उपधारा (5) में। मुद्दा यह है कि, धारा 8ए होगा 12.1.2015 को मौजूदा पट्टे पर लागू (संशोधित होने पर)। एमएमडीआर अधिनियम अधिसूचित किया गया था), जैसा कि गैर-आवेदक का तर्क था याचिकाकर्ता की इसके बाद तुरंत और विस्तार से जांच की

जाएगी। इसलिए, पहली आकस्मिकता नवीनीकृत खनन पट्टों तक फैली हुई है, जो 31.3.2030 से पहले समाप्त होने वाले थे।

दूसरी बात, वाक्यांश का उपयोग- "नवीनीकरण अंतिम बार हुआ", के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है इसमें कोई संदेह नहीं है, कि तत्काल दूसरी आकस्मिकता मौजूदा स्थिति का अनुमान लगाती है (पहला, दूसरा या बाद का) नवीनीकरण, पट्टाधारक के पक्ष में। पहली और दूसरी आकस्मिकता के बीच का अंतर, तारीख कब है खनन पट्टे का नवीनीकरण समाप्त होने वाला था। पहला आकस्मिकता, नवीनीकृत खनन पट्टों पर लागू होती है, जो पहले समाप्त हो जाएगी 31.3.2030. तत्काल- दूसरी आकस्मिकता, नवीनीकृत पर लागू होती है खनन पट्टे, जो 31.3.2030 के बाद समाप्त हो जायेंगे। अनुभाग का अवलोकन संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के 8ए से पता चलता है कि दूसरी आकस्मिकता है इसका उद्देश्य मौजूदा लीज अवधि को बढ़ाना है, न कि इसे कम करना। इसलिए, यदि मौजूदा नवीनीकरण की अवधि आगे बढ़ जाएगी 31.3.2030, नवीनीकरण द्वारा ही विचारित अवधि रही है संरक्षित करने का आदेश दिया गया है।

तीसरी बात, जिस व्यवस्था को लागू करने की मांग की गई है उसका भी एक संदर्भ है मूल अनुदान. के तहत योजना/पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग की गई है संशोधित एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8A(3) का उद्देश्य है संरक्षित किया जाए यहां तक कि उन स्थितियों में भी जहां एक खनन पट्टाधारक खनन कर रहा है (या रहा है)। नवीनीकरण के तहत खनन कार्य पर। की मूल पट्टा अवधि के बाद से पचास वर्ष को सर्वव्यापी नियम के रूप में अपनाया गया है, तीसरा आकस्मिकता, का उद्देश्य पट्टाधारक को उपचार का लाभ देना है मूल पट्टा अवधि पचास वर्ष है। इसलिए नवीनीकरण के दौरान भी अवधि, यदि खनन पट्टे की अवधि (से अधिक) बढ़ जाएगी

नवीनीकरण अवधि), मूल पट्टे को पचास वर्ष मानकर तीसरे के तहत पट्टाधारक उक्त लाभ का हकदार होगा आकस्मिकता।

धारा 8A(5) द्वारा शासित पट्टों के लिए, उपरोक्त तीन में से आकस्मिकताएं, वह आकस्मिकता जो पट्टे की अवधि को दूर तक बढ़ाएगी, लागू होगा.

19. धारा 8A(6) के तहत एक समान आकस्मिकता प्रदान की गई है गैर-कैप्टिव उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले खनन पट्टों के संदर्भ में। इस के साथ साथ साथ ही, उन्हीं तीन आकस्मिकताओं पर विचार किया जाता है। सबसे पहले, अवधि 31.3.2020 से पहले समाप्त होने वाले सभी नवीनीकरणों की "...बढ़ाई जाएगी और होगी इसे 31.3.2020 तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा, "...से प्रभाव से अंतिम बार नवीनीकरण की अवधि की समाप्ति की तारीख..." दूसरे, यदि किसी भी स्थिति में नवीनीकरण की अवधि वास्तव में आगे बढ़ जाएगी 31.3.2020 -फिर निर्धारित नवीनीकरण अवधि के पूरा होने तक। तीसरा, मूल पट्टे को दिनांक से पचास वर्ष तक बढ़ाने के लिए मूल पट्टा प्रदान करना. धारा 8ए(6) द्वारा शासित पट्टों के लिए आकस्मिकता, जैसा कि सबसे अंत में समाप्त होगी, पर लागू होगी पट्टाधारक. यहां कोई और चर्चा रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, क्योंकि पिछले पैराग्राफ में चर्चा, के लिए पूरी तरह से लागू है संशोधित एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8A(6) की व्याख्या, सिवाय इसके कि के लिए दिनांक 31.3.2020 का प्रतिस्थापन (एमएमडीआर की धारा 8A(6) के अनुसार) अधिनियम) 31.3.2030 के स्थान पर (एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8A(5) के तहत)।

20. को लेकर प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच गंभीर विवाद चल रहा है धारा 8A(3), 8A(5) और 8A(6) का एमएमडीआर अधिनियम. जबकि की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क याचिकाकर्ता-सामान्य कारण यह है कि उपधारा (3), (5) और का

लाभ (6) धारा 8ए का विस्तार केवल ऐसे खनन पट्टों तक ही होगा जो थे संशोधन की शुरूआत की तारीख पर कायम रहना - 12.1.2015; यह यह पट्टाधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क है उपर्युक्त अभिधारणा, विद्वान परामर्शदाता के हाथों गैर-आवेदकों के अनुसार, यह पूरी तरह गलत धारणा है और इसके परिणामस्वरूप गलत व्याख्या होगी एमएमडीआर अधिनियम की संशोधित धारा 8ए की।

21. जहां तक एमएमडीआर की धारा 8ए की विवादित व्याख्या का संबंध है अधिनियम का संबंध है, पहला तर्क विद्वान वकील द्वारा आगे बढ़ाया गया याचिकाकर्ता, धारा 8A की उप-धारा (9) पर स्थापित किया गया था। यह आग्रह किया गया था, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि एमएमडीआर की धारा 8A का लाभ अधिनियम, ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगा जहां "नवीनीकरण अस्वीकार कर दिया गया था", या जहां खनन पट्टा "निर्धारित" किया गया था, या जहां खनन किया गया था पट्टा "व्यपगत" हो गया था। यह दावा किया गया था, कि मूल अनुदान की समाप्ति या नवीनीकरण का मतलब यह समझा जाना चाहिए कि पट्टा चाहे जो भी हो दी गई (मूल, या नवीनीकरण) "व्यपगत" हो गई थी। और इसलिए, यह क्रिस्टल था विद्वान वकील के अनुसार, स्पष्ट है कि उपधारा (3), (5) और (6)। धारा 8ए, केवल उन पट्टाधारकों पर लागू होगी जिनके पास आजीविका है 12.1.2015 को खनन पट्टा।

22. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील आगे बढ़ाई गई, इसमें गौर किया गया उपरोक्त अनुच्छेद का विद्वानों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है पट्टाधारकों के लिए परामर्श. की ओर से यह दलील दी गयी पट्टाधारकों, कि शब्द "अस्वीकृति", "दृढ़ संकल्प" और "चूक" थे कला की शर्तें, विभिन्न आकस्मिकताओं/स्थितियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं। विद्वान परामर्शदाता के अनुसार इन शर्तों पर

अलग-अलग विचार किया गया है एमएमडीआर अधिनियम (और उसके तहत बनाए गए नियमों) के तहत अत्यावश्यक आवश्यकताएँ। और कि, उक्त शर्तों को उससे आगे की स्थितियों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसका प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है। इसलिए यह दावा किया गया कि मूल अनुदान या नवीनीकरण की समाप्ति, स्वयं को बाहर नहीं करेगी धारा 8ए की प्रयोज्यता।

23. जहाँ तक शब्दों का प्रश्न है "नवीनीकरण अस्वीकृत कर दिया गया था" (अनुभाग में प्रयुक्त) एमएमडीआर अधिनियम के 8ए(9) का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था, कि यह स्पष्ट था तैनात किए गए शब्दों से, चिंतनशील आकस्मिकता ही लागू होती है ऐसी स्थिति में जहां नवीनीकरण के लिए एक आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। अर्थात्, खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया था एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) या (3), नियम 24ए के साथ पढ़ें खनिज रियायत नियम, और उसके बाद, नवीनीकरण के लिए अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था. "संकल्प" शब्द के लिए अवलम्बन रखा गया नियम 27(4), 27(5), 29, 37(3) एवं भाग IX खंड 2, खनिज का प्रपत्र K रियायत नियम. यह तर्क दिया गया कि "संकल्प" शब्द था उन स्थितियों के लिए तैनात किया गया है जहां लीज अवधि को लाया जा सकता है पट्टाधारक द्वारा की गई चूक के कारण समाप्ति। उदाहरण के लिए, रॉयल्टी के भुगतान में चूक या मृतकों के भुगतान में चूक किराया। डिफ़ॉल्ट परिकल्पित लीज शर्तों का उल्लंघन भी हो सकता है खनिज रियायत नियमों के नियम 27(1) या (2) या (3) के तहत। एक खनन पट्टा भी निर्धारित किया जा सकता है, यदि पट्टाधारक ने कोई अधिकार हस्तांतरित किया हो, खनिज रियायत के उल्लंघन में, खनन पट्टे में स्वामित्व या हित नियम। और कुछ अन्य परिभाषित अत्यावश्यकताओं के लिए। जहां तक शब्द "चूक" का सवाल है धारा 8ए(9) में प्रयुक्त का संबंध है, सीखे गए अनुसार वही पट्टाधारकों के लिए परामर्श, नीचे विचार की गई अत्यावश्यकताओं से संबंधित है

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4ए(4), और खनिज के नियम 28 और 28ए रियायत नियम. "चूक" शब्द का प्रयोग केवल वहीं किया गया है पट्टाधारक ने स्थिति में न होने के कारण चूक की है खनन कार्यों को निरंतर जारी रखना (या न चलाने के लिए)। दो वर्ष की अवधि. उपर्युक्त अत्यावश्यकताओं में से किसी एक के कारण, a उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के तहत खनन पट्टा समाप्त हो जाएगा।

24. हम विशेष निकालने की आवश्यकता नहीं समझते पट्टाधारकों के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन प्रावधानों पर भरोसा किया गया। हम हैं इस तर्क को स्वीकार करने में संतुष्ट हूं कि शर्तें "नवीनीकरण किया गया है अस्वीकृत", "दृढ़ संकल्प" और "चूक" शब्द अलग-अलग के लिए उपयोग किए जाते हैं एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत आकस्मिकताएं/स्थितियां/आवश्यकताएं, और खनिज रियायत नियम. हमारा यह भी विचार है कि ये शर्तें नहीं हैं एमएमडीआर अधिनियम, या खनिज रियायत नियमों के तहत उपयोग किया जाता है। मूल अनुदान अवधि की समाप्ति के संदर्भ में, या के संदर्भ में नवीनीकरण अवधि की समाप्ति. इसलिए हमारे लिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं है याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि धारा 8A(9) धारा 8ए की प्रयोज्यता को बाहर करने का वैध आधार हो सकता है, पट्टाधारकों के दावे, जहां पट्टे या नवीनीकरण की अवधि थी 12.1.2015 से पहले समाप्त हो गया।

25. हमने पिछले पैराग्राफ में भी जो निष्कर्ष निकाला है संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के "उद्देश्यों और कारणों" से उभरता है। जिस उद्देश्य से तत्काल संशोधन किया गया संसद, जिसके द्वारा संशोधित धारा 8ए को इसमें शामिल किया गया था एमएमडीआर अधिनियम से पता चलता है कि पिछले मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप अलग-अलग परिणाम हुए एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या, और

कथित दूसरे और उसके बाद के कारण खनन उद्योग को कठिनाई हुई नवीनीकरण राज्य सरकार के पास बिना किसी देरी के लंबित है निर्णय, तत्काल संशोधन के पारित होने का अवसर था। के कथन के निम्नलिखित अंशों से उपरोक्त स्थिति उभरती है "वस्तुएँ और कारण":

> “3. खनन क्षेत्र को कई मुकदमों का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ साल. खनन क्षेत्र से सम्बंधित महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले सुनाए गए हैं प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का मुद्दा जिसकी प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है खनिज रियायतें प्रदान करने के संबंध में।
>
> 4. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 का वर्तमान कानूनी ढांचा इसकी अनुमति नहीं देता है खनिज रियायतों की नीलामी. खनिज की नीलामी रियायतों से आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार खनिज संसाधनों के मूल्य का बढ़ा हुआ हिस्सा भी मिलेगा। खनिज रियायतों के नवीनीकरण से संबंधित कानून के कुछ प्रावधान त्वरित निर्णय लेने में भी कमी पाई गई है। फलस्वरूप नये अनुदान में मंदी आ गयी है रियायतें और मौजूदा का नवीनीकरण। परिणामस्वरूप, खनन क्षेत्र ने उत्पादन में गिरावट दर्ज करना शुरू कर दिया जिससे प्रभावित हुआ विनिर्माण क्षेत्र जो काफी हद तक कच्चे माल पर निर्भर करता है खनन क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया। इसलिए सरकार को यह महसूस हुआ है खनन क्षेत्र की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है और इसके मूल में मौजूद बुनियादी संरचनात्मक दोषों को दूर करने के लिए भी वर्तमान गतिरोध.

5. इन समस्याओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 12 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित किया गया था। वर्तमान विधेयक इसका स्थान लेगा यह अध्यादेश. यह विधेयक निम्नलिखित के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

(i) विवेक को ख़त्म करना;

(ii) खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता में सुधार;

(iii) प्रक्रियाओं को सरल बनाना;

(iv) प्रशासन में देरी को समाप्त करना, ताकि शीघ्रता से कार्य किया जा सके और देश के खनिज संसाधनों का इष्टतम विकास;

(v) सरकार के लिए मूल्य का एक बढ़ा हुआ हिस्सा प्राप्त करना देश के खनिज संसाधन; और

(vi) निजी निवेश और नवीनतम तकनीक को आकर्षित करना;

6. एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2015 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) विवेकाधिकार को हटाना: नीलामी आवंटन का एकमात्र तरीका होगा: संशोधन का उद्देश्य अत्यधिक पारदर्शिता लाना है खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए नीलामी तंत्र। का कार्यकाल खनिज पट्टों की अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है साल। पट्टों के नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) खनन क्षेत्र को प्रोत्साहन: खनन उद्योग रहा है दूसरे और बाद के नवीनीकरण शेष रहने के कारण व्यथित हैं लंबित। दरअसल, इससे बड़ी संख्या में खदानें बंद हो गई हैं। विधेयक इस मुद्दे को भी संबोधित करता है। विधेयक यह प्रावधान करता है कि खनन पट्टे को उनके अंतिम नवीनीकरण की तारीख से बढ़ा हुआ माना जाएगा 31 मार्च, 2030 (कैप्टिव खानों के मामले में) और 31 मार्च तक, 2020 (व्यापारी खनिकों के लिए) या नवीनीकरण पूरा होने तक पहले ही प्रदान किया जा चुका है, यदि कोई हो, या अनुदान की तारीख से पचास वर्ष की अवधि ऐसी छुट्टी की, जो भी बाद में हो।"

(जोर हमारा है)

ऊपर दिए गए उद्धरण के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि धारा 8ए को एमएमडीआर अधिनियम में सम्मिलित करने से कठिनाइयों का समाधान किया गया था पट्टाधारकों को अन्य कारणों के अलावा दूसरे कारणों से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है नवीनीकरण के लिए बाद में आए आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया गया राज्य सरकार का. एमएमडीआर अधिनियम में त्वरित संशोधन, सभी खनन के लिए पचास वर्षों की एक समान मूल अनुदान अवधि की शुरुआत की गई पट्टाधारक। इसमें मूल की समाप्ति के बाद नवीनीकरण को भी शामिल नहीं किया गया है पट्टे की अवधि. तदनुसार, अब कोई भी नवीनीकरण आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकेगा 12.1.2015). हमारे विचार में, धारा 8A की उपधारा (5) और (6) के तहत, ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था कैप्टिव/नॉन-कैप्टिव खदानें, तक जारी रखने की हकदार होंगी 31.3.2030/31.3.2020. संशोधन के लिए "उद्देश्य और कारण"। एमएमडीआर अधिनियम का उद्देश्य उस स्थिति को सुधारना है जो उभरी

है एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या, जैसा कि वे अब तक अस्तित्व में थे पहले। तत्काल संशोधन का उद्देश्य भी इसका समाधान करना था खनन उद्योग की शिकायतें "दूसरे और बाद के" के कारण नवीनीकरण" लंबित है। और इसलिए भी, क्योंकि कानून के प्रावधान नवीनीकरण के संबंध में कमी पाई गई थी। उपरोक्त दृश्य भी यही है इस तथ्य से समर्थित, कि धारा 8ए(9) ऐसी स्थिति से संबंधित है जिसमें "... नवीनीकरण अस्वीकार कर दिया गया है..."। इसलिए यह स्पष्ट है कि उप-धाराएँ संशोधित एमएमडीआर अधिनियमधारा 8A के (5) और (6) > लक्ष्यित हैं ऐसी स्थितियाँ, जिनमें नवीनीकरण के लिए आवेदन (वैध रूप से किया गया) हो उपेक्षित रहा. इसलिए, पट्टाधारक की कोई गलती नहीं होने पर, वह ऐसा करेगा मनमाने पूर्वाग्रह का शिकार होना। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तब से 12.1.2015 के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता नवीनीकरण के लिए इसे वैध रूप से किया गया माना जाएगा, किया जाना चाहिए 12.1.2015 से पहले बनाये गये हैं। हमारा विचार है, कि बाहर उप-के अंतर्गत तीन आकस्मिकताओं पर विचार किया गया धारा 8A(5) और 8A(6), ऊपर उल्लिखित आकस्मिकताओं में से पहली सकारात्मक रूप से संबंधित है स्थिति, जिसमें नवीनीकरण के लिए वैध रूप से किए गए आवेदन लंबित थे राज्य सरकार के हाथों बिना किसी अंतिम निर्णय के। क्योंकि नवीनीकरण आवेदन के अभाव में पट्टाधारक हो सकता है खनन जारी रखने के प्रति उन्होंने पहले ही अपनी उदासीनता व्यक्त कर दी है परिचालन. इसलिए तार्किक रूप से, शब्द "... की तारीख से प्रभावी हैं अंतिम बार नवीनीकरण की अवधि की समाप्ति...", समाप्त हो चुकी अवधि से संबंधित होनी चाहिए 12.1.2015 से पूर्व का पट्टा, जिसके संबंध में वैध आवेदन पत्र नवीनीकरण पहले ही हो चुका था।

26. हम आगे दिए गए विवाद को स्वीकार करने में भी आश्वस्त महसूस करते हैं पट्टाधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के हाथ, कि शब्द "... पिछले

नवीनीकरण की अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी बनाया..." को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। हमारे सुविचारित विचार में, ऐसा नहीं है उपरोक्त शब्दों में अस्पष्टता. उद्धृत शब्दों का स्पष्ट वाचन, इससे एक और केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अर्थात् स्थिति की धारा 8A की उप-धारा (5) और (6) के तहत विचार किया गया संशोधित एमएमडीआर अधिनियम (जिसमें उपरोक्त दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है), ऐसी स्थिति शामिल है जब नवीनीकरण द्वारा लीज अवधि पर विचार किया जाता है 31.3.2030/31.3.2020 से पहले समाप्त होने वाला है। हम इससे संतुष्ट हैं स्पष्ट करते हुए कहा कि उपरोक्त के प्रयोग से स्थिति पर विचार किया गया शब्द, उस पट्टाधारक तक विस्तारित होंगे जिसने एक वैध आवेदन दायर किया था राज्य सरकार को नवीनीकरण के लिए, जिस पर अभी विचार किया जाना बाकी था 12.1.2015 से पहले निपटाया गया। तात्कालिक स्थिति को इससे बाहर नहीं रखा गया है संशोधित की धारा 8ए(9) के तहत विचार की गई आकस्मिकताएं एमएमडीआर अधिनियम। तत्काल पैराग्राफ में दर्ज कारणों के लिए भी, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में (जिसमें संशोधित एमएमडीआर की धारा 8A अधिनियम, पर विचार किया गया है और व्याख्या की गई है), हम इसे मानने से संतुष्ट हैं संशोधित एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8A की प्रयोज्यता न केवल आवश्यक है उन पट्टाधारकों तक विस्तारित करें जिनकी मूल पट्टा/नवीनीकरण पट्टा अवधि पूरी नहीं हुई थी समाप्त हो गया है, लेकिन इसका विस्तार उन पट्टाधारकों पर भी होगा जिनकी अवधि पट्टा/नवीनीकरण 12.1.2015 से पहले समाप्त हो गया था और संबंधित कम से कम बारह पट्टाधारकों ने नवीनीकरण के लिए वैध आवेदन दिया था पट्टाधारक के मौजूदा पट्टे से कुछ महीने पहले (मूल, पहला, दूसरा या) आगामी) समाप्त होने वाला था, और जिसका आवेदन नहीं किया गया है विचार किया गया और अस्वीकृत कर दिया गया।

27. यहां ऊपर देखी गई स्थिति चाहे जो भी हो, यह अनिवार्य है हमें यह स्पष्ट करना होगा कि लीज अवधि के विस्तार का लाभ एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ए के अंतर्गत अभिनिर्धारित उपलब्ध है, बशर्ते कि आगे की अधिभावी शर्त, अर्थात्, "... सभी नियम और शर्तें पट्टे का अनुपालन किया गया है"। जो पट्टाधारक संतुष्ट नहीं है पट्टे की कोई भी आवश्यक शर्त, उदाहरण के लिए, निर्धारित मंजूरी/अनुमोदन/सहमति, लाभ के हकदार नहीं होंगे संशोधित की धारा 8A की उप-धारा (5) या (6) के तहत विस्तारित एमएमडीआर अधिनियम।

28. के निर्वाह के संदर्भ में इस मुद्दे को संबोधित किया है एक खनन पट्टा, धारा 8 और 8A का एमएमडीआर अधिनियम में, हमने उस क्षेत्र को काफी हद तक कवर कर लिया है जिसकी आवश्यकता थी पार किया गया हालाँकि, एक और पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है निपटने की जरूरत है. के सामूहिक पाठन से भी यही बात सामने आती है एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4ए(4) और खनिज के नियम 28 और 28ए रियायत नियम. धारा 4A(4) को पहले धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था 4ए 10.2.1987 से प्रभावी, निम्नानुसार:

> “4-ए. पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टों की समाप्ति.-
>
> xxx xxx xxx
>
> (4) जहां खनन पट्टा धारक खनन करने में विफल रहता है निष्पादन की तारीख के बाद दो साल की अवधि के लिए संचालन पट्टे पर देना या खनन कार्य शुरू कर देना बंद कर दिया है दो वर्ष की अवधि के लिए, पट्टा समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि या, जैसे मामला यह हो सकता है, खनन कार्यों को बंद करना: बशर्ते कि राज्य सरकार, द्वारा किए गए आवेदन

पर इस उप-धारा के तहत इसकी समाप्ति से पहले ऐसे पट्टे का धारक और इस बात से संतुष्ट होने पर कि पट्टा धारक के लिए यह संभव नहीं होगा खनन कार्य करना या ऐसे कार्यों को जारी रखना उसके नियंत्रण से बाहर के कारण, ऐसी शर्तों के अधीन, एक आदेश बनाते हैं जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, इस आशय से कि ऐसा पट्टा समाप्त नहीं होगा: बशर्ते कि राज्य सरकार, किसी आवेदन पर पट्टे के धारक ने छह महीने की अवधि के भीतर जमा किया इसकी समाप्ति की तारीख और इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा शुरू नहीं हुआ है या धारक के नियंत्रण से परे कारणों से बंद किया गया था पट्टे की, ऐसे संभावित या पूर्वव्यापी से पट्टे को पुनर्जीवित करें तारीख जो वह उचित समझे लेकिन पट्टे की समाप्ति की तारीख से पहले नहीं: बशर्ते कि दूसरे प्रावधान के तहत कोई भी पट्टा पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा पट्टे की पूरी अवधि के दौरान दो बार से अधिक के लिए।"

(जोर हमारा है)

उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि जहां खनन धारक है पट्टा, निरंतर अवधि के लिए खनन कार्य नहीं करता है दो साल बाद उनका खनन पट्टा समाप्त हो जाएगा। यह विद्वानों का विवाद था याचिकाकर्ता के लिए वकील - सामान्य कारण, साथ ही विद्वान का भी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, कि धारा 4A(4) का संचालन है स्वचालित, और किसी आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि जैसे ही पट्टाधारक ने इसमें शामिल न होने की चूक की है खनन जारी रखने (या वास्तव में खनन न करने) की स्थिति

परिचालन, लगातार दो वर्षों की अवधि के लिए, पट्टा समाप्त हो जाएगा। उपरोक्त दो अत्यावश्यकताओं को पहली और दूसरी के रूप में संदर्भित किया जाएगा आकस्मिकता क्रमशः, इसके बाद।

29. विद्वान वकील के अनुसार, ऐसे के लिए एकमात्र उपाय उपलब्ध है पट्टाधारक, पट्टे को समाप्त होने से बचाने के लिए, एक आवेदन प्रस्तुत करता है, या तो दो वर्ष की अवधि (गैर-खनन) की समाप्ति से पहले संचालन), या उसके बाद। राज्य सरकार संतुष्ट होने पर कि जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, खनन कार्य बंद नहीं किया गया पट्टाधारक के नियंत्रण से परे कारणों से, कोई आदेश दिया जा सकता है पहली आकस्मिकता, कि पट्टा समाप्त नहीं होगा। और दूसरे में आकस्मिकता, कि पट्टा पुनः भौतिक हो जाएगा।

30. हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है, कि महत्वपूर्ण निहित अधिकार पट्टाधारक की आय में बिना अवसर दिए कटौती की जा सकती है सक्षम प्राधिकारी की धारणा(ओं) को अस्वीकार करें, अर्थात् पट्टाधारक खनन नहीं कर सकता था (या वास्तव में नहीं किया था)। संचालन, दो वर्षों की निरंतर अवधि के लिए। हमारा तत्काल चिंतन, खनिज के नियम 28 के माध्यम से पुष्टि की जाती है रियायत नियम. इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “28. पट्टों का व्यपगत होना - (1) इस नियम की अन्य शर्तों के अधीन जहां खनन कार्य एक अवधि के भीतर शुरू नहीं किया जाता है पट्टे के निष्पादन की तारीख से वर्ष (sic. दो वर्ष), या है इसके बाद एक वर्ष (लगभग दो वर्ष) की निरंतर अवधि के लिए बंद कर दिया गया ऐसे परिचालनों की शुरुआत, राज्य सरकार, एक द्वारा करेगी

आदेश दें, खनन पट्टे को व्यपगत घोषित करें और सूचित करें पट्टेदार को घोषणा.

(2) जहां कोई पट्टेदार खनन कार्य शुरू करने में असमर्थ है निष्पादन की तारीख से एक वर्ष (जैसे दो वर्ष) की अवधि खनन पट्टा, या उससे अधिक अवधि के लिए खनन कार्य बंद कर देता है उसके नियंत्रण से परे कारणों से, वह एक वर्ष (लगभग दो वर्ष) कर सकता है समझाते हुए राज्य सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करें इसके लिए कारण, इसकी समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले अवधि।

(3) उप-नियम (2) के तहत प्रत्येक आवेदन शुल्क के साथ होगा 200 रुपये का.

(4) राज्य सरकार इसके तहत आवेदन प्राप्त होने पर उपनियम (2) एवं पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर खनन शुरू न होने के कारणों की सत्यता परिचालन या उसे बंद करने की तारीख से पहले एक आदेश पारित करें जिसे बढ़ाने या अस्वीकार करने पर पट्टा अन्यथा समाप्त हो जाता पट्टे की अवधि बढ़ाएँ:

बशर्ते कि जहां राज्य सरकार आवेदन प्राप्त होने पर उप-नियम (2) के तहत तिथि की समाप्ति से पहले कोई आदेश पारित नहीं करता है जिस पर पट्टा अन्यथा समाप्त हो जाता, पट्टा होगा राज्य द्वारा आदेश पारित होने तक इसे बढ़ाया हुआ माना जाएगा सरकार या दो वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो।

स्पष्टीकरण 1. - जहां खनन प्रारंभ न होना निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर संचालन खनन पट्टा किसके कारण होता है-

(ए) सतही अधिकारों के अधिग्रहण में देरी; या

(बी) पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का कब्ज़ा प्राप्त करने में देरी; या

(सी) मशीनरी की आपूर्ति या स्थापना में देरी; या

(डी) बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में देरी, या कोई वित्तीय संस्थान; या

(ई) उस उद्योग में खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करना जिसका पट्टेदार है मालिक या जिसमें उसका नियंत्रण 50% से कम न हो दिलचस्पी,

और पट्टेदार निम्नलिखित द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम है विधिवत शपथ पत्र के आधार पर राज्य सरकार विचार कर सकती है परिचालन शुरू न होने के लिए पर्याप्त कारण एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि (अर्थात् दो वर्ष)।

स्पष्टीकरण 2. - जहां खनन कार्यों को बंद करने के लिए ऐसी शुरुआत के बाद दो साल की निरंतर अवधि संचालन किसके कारण होता है -

(ए) किसी वैधानिक या न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश; या

(बी) परिचालन अत्यधिक अलाभकारी होता जा रहा है; या

(सी) हड़ताल या तालाबंदी, और पट्टेदार निम्नलिखित द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम है विधिवत शपथ पत्र के आधार पर राज्य सरकार विचार कर सकती है लगातार परिचालन बंद करने के पर्याप्त कारण एक वर्ष से अधिक की अवधि (अर्थात् दो वर्ष)।

स्पष्टीकरण 3. - खनन पट्टेदार के मामले में जिसने खनन किया है टोही संचालन या खनन के मामले में पट्टेदार जिसकी पूंजी खदान विकास में रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना है। 200 करोड़ और जहां खदान विकास में दो से अधिक समय लगने की संभावना है वर्ष, राज्य सरकार इसे पर्याप्त कारण मानेगी लगातार अवधि तक खनन कार्य शुरू न होना दो वर्ष से अधिक।"

(जोर हमारा है)

ऊपर दिए गए उप-नियम (1) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को एक आदेश पारित करने और इस प्रकार घोषणा करने का आदेश दिया गया है कि एक खनन पट्टा समाप्त हो गया था। यह उपनियम (1) का भी आदेश है पूर्वोक्त, कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाना चाहिए पट्टाधारक को सूचित किया गया। धारा 4A(4) के संयुक्त पाठन पर और नियम 28(1), हम यह मानते हुए संतुष्ट हैं कि धारा के तहत एक खनन पट्टा 4A(4) को तब तक व्यपगत नहीं माना जाएगा जब तक राज्य सरकार एक आदेश पारित करता है, खनन पट्टे को समाप्त घोषित करता है, और आगे इसकी सूचना पट्टाधारक को देता है।

31. खनिज रियायत नियमों का नियम 28(4) एक स्थिति को पूरा करता है जिसमें एक पट्टाधारक ने एक आवेदन दायर किया है कि उसका पट्टा दिया जाए भले

ही खनन कार्य नहीं किया जा सके, फिर भी इसे जारी रखने की अनुमति दी गई दो की लगातार अवधि के लिए जारी (या वास्तव में आगे नहीं बढ़ाया गया था)। साल। नियम 28(4) के तहत प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार, ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, आदेश पारित नहीं करता है तो पट्टा माना जाएगा तब तक बढ़ाया गया, जब तक राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कोई आदेश पारित नहीं कर दिया गया। इससे यह भी पुष्टि होती है कि खनन पट्टे का समाप्त होना स्वचालित नहीं है। नियम 28(2) के तहत खनन पट्टे का संचालन न होने के बावजूद, मामले में पट्टाधारक ने विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया है खनन कार्य प्रारंभ न होना, या इसके कारण खनन कार्यों को बंद करने पर लीज अवधि मानी जाएगी आदेश पारित होने की तारीख तक या दो की अवधि तक जारी रहे हैं नियोजित पट्टा अवधि से अधिक वर्ष (यदि ऐसा कोई आदेश नहीं है)। उत्तीर्ण)। उपरोक्त निष्कर्ष आगे दी गई दलीलों को खारिज करते हैं अनावेदक-याचिकाकर्ता और भारत संघ की ओर से, वह चूक (एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4A(4) के तहत विचार किया गया) स्वचालित है, और कि, किसी पट्टे को समाप्त होने के लिए कोई स्पष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

32. ऊपर दर्ज विचारों के आधार पर, हम अपना सारांश प्रस्तुत करते हैं निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) एक पट्टाधारक के पास एक मौजूदा खनन पट्टा होगा, यदि अवधि मूल अनुदान का हिस्सा 12.1.2015 को अभी भी मुद्रा में था। इसके अतिरिक्त, एक पट्टाधारक जिसका मूल पट्टा तब से है समाप्त हो गया है, यदि मूल पट्टा है तो अभी भी एक जीवित पट्टा होगा नवीनीकरण होने के बाद भी नवीनीकरण की अवधि

अभी भी चालू थी 12.1.2015. ऐसा पट्टाधारक लाभ का हकदार होगा संशोधित एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8A।

(ii) एक पट्टाधारक जिसने नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था खनन पट्टा (जो 12.1.2015 से पहले समाप्त होने वाला था), पर मौजूदा पट्टा समाप्त होने से कम से कम बारह महीने पहले, असंशोधित एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत और खनिज रियायत नियम, नहीं माने जायेंगे पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद वैध/मौजूदा पट्टाधारक। इसलिए संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान नहीं होंगे ऐसे पट्टाधारक के लाभ को सुनिश्चित करें।

(iii) एक पट्टाधारक जिसने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है खनन पट्टे का मूल/पहला या बाद का नवीनीकरण, कम से कम मौजूदा पट्टा समाप्त होने से बारह महीने पहले, और आगे विचारार्थ, ऐसा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, किया जायेगा वैध/मौजूदा पट्टाधारक नहीं माना जाता है। प्रावधानों एमएमडीआर अधिनियम की संशोधित धारा 8ए के अंतर्गत यह सुनिश्चित नहीं किया जाएगा स्पष्ट बहिष्करण के कारण ऐसे पट्टाधारक को लाभ धारा 8A(9) के अंतर्गत उपरोक्त अत्यावश्यकता पर विचार किया गया। संशोधित एमएमडीआर अधिनियम।

(iv) एक पट्टाधारक जिसने "प्रथम नवीनीकरण" के लिए आवेदन किया है मूल खनन पट्टा, कम से कम बारह महीने पहले मूल पट्टा समाप्त होने वाला था, और ऐसा आवेदन समाप्त नहीं हुआ है अस्वीकृत कर दिया गया है, वैध पट्टाधारक माना जाएगा की समाप्ति तक खनन कार्य जारी रखने का एक स्थायी अधिकार 18.7.2014 के बाद दो वर्ष, अर्थात 17.7.2016 तक, जैसा कि स्पष्ट है असंशोधित और संशोधित नियम के संयुक्त वाचन से खनिज रियायत नियमावली की धारा 24ए. ऐसे पट्टाधारक

होंगे की धारा 8A की उपधारा (5) और (6) का लाभ मिलेगा संशोधित एमएमडीआर अधिनियम।

(v) एक पट्टाधारक जो दूसरा (तीसरा या अगला) स्थानांतरित हुआ था असंशोधित एमएमडीआर की धारा 8(3) के अंतर्गत नवीनीकरण आवेदन अधिनियम, नवीनीकृत पट्टे से कम से कम बारह महीने पहले देय था समाप्त हो रहा है, और जिनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया था और अस्वीकृत (हालाँकि इसके तहत किसी भी लाभ का हकदार नहीं है एमएमडीआर अधिनियम की असंशोधित धारा 8ए और संशोधित नियम 12.1.2015 तक खनिज रियायत नियमों के 24ए(6)) अभी भी धारा 8A की उपधारा (5) और (6) का लाभ मिलेगा स्थिति को देखते हुए संशोधित एमएमडीआर अधिनियम खान एवं खनिज (विकास एवं) द्वारा उपचारित विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015।

(vi) एमएमडीआर की धारा 8ए के संशोधन के परिणामस्वरूप अधिनियम, उप-धारा (5) और (6) के माध्यम से पेश किया गया शासन उसमें, तीन आकस्मिकताओं का प्रावधान है जहां लाभ होता है उन पट्टाधारकों के लिए बढ़ा दिया गया है जिनकी पट्टा अवधि पहले थी नवीनीकरण द्वारा बढ़ाया गया। सबसे पहले, एक पट्टाधारक के लिए जिसका नवीनीकरण अवधि 12.1.2015 से पहले समाप्त हो गई थी, और पट्टाधारक ने कम से कम बारह बार नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था पट्टाधारक का मौजूदा पट्टा समाप्त होने के कुछ महीने पहले, और जिनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया है और खारिज कर दिया गया है लीज अवधि 31.3.2030/31.3.2020 तक बढ़ाई जाएगी (क्रमशः कैप्टिव/गैर-कैप्टिव खानों के मामले में)। इसके अतिरिक्त, एक पट्टाधारक जिसकी नवीनीकरण की अवधि समाप्त हो जाएगी 12.1.2015 के बाद, लेकिन 31.3.2030/31.3.2020 से पहले, पट्टा अवधि 31.3.2030/31.3.2020 तक

बढ़ाई जाएगी (में) क्रमशः कैप्टिव/गैर-कैप्टिव खानों का मामला)। दूसरा, कहां खनन पट्टे का नवीनीकरण पहले से ही एक अवधि तक बढ़ाया जाता है 31.3.2030/31.3.2020 से आगे (बंदी/गैर-बंदी के मामले में) खानों, क्रमशः), ऐसे पट्टाधारकों की पट्टा अवधि होगी नवीनीकरण द्वारा अपेक्षित वास्तविक अवधि तक जारी रहेगा आदेश देना। तीसरा, पट्टाधारक को इलाज का लाभ मिलेगा मूल पट्टा अवधि पचास वर्ष है। तदनुसार, सम नवीनीकरण अवधि के दौरान, यदि खनन पट्टे की अवधि का उपचार करके (नवीनीकरण अवधि से आगे) बढ़ाया जाएगा मूल पट्टे के रूप में पचास वर्ष का, पट्टाधारक हकदार होगा ऐसे लाभ के लिए.

उपरोक्त में से तीन आकस्मिकताओं को उपधाराओं के अंतर्गत प्रदान किया गया है धारा 8A के (5) और (6), आकस्मिकता का विस्तार होगा पट्टे की अवधि सबसे दूर, के लाभ को सुनिश्चित करेगी पट्टाधारक.

(vii) धारा 4A(4) पर हमारे द्वारा दी गई व्याख्या के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम, और खनिज रियायत नियमों के नियम 28, हम कर सकते हैं निम्नलिखित निष्कर्ष निकालें. सबसे पहले, जब तक कोई आदेश न हो राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा घोषित करते हुए पारित किया गया समाप्त हो गया है, तो खनन पट्टा विद्यमान माना जाएगा, पट्टे द्वारा प्रदान की गई पट्टा अवधि की समाप्ति की तारीख तक दस्तावेज़। दूसरे, उन स्थितियों में जहां एक एप्लिकेशन है एक पट्टाधारक द्वारा दायर किया गया है, जब वह (या इसके लिए) स्थिति में नहीं है वास्तव में नहीं) निरंतर खनन कार्य जारी रखना दो वर्ष की अवधि के लिए लीज अवधि नहीं मानी जाएगी राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई आदेश पारित होने तक व्यपगत आवेदन पत्र। जहां कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, वहां पट्टा होगा मूल पट्टा अवधि से आगे बढ़ा हुआ माना जाएगा, दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए. तीसरा, एक पट्टाधारक के

पास चूक का सामना करना पड़ा, संशोधन के किसी भी लाभ का हकदार नहीं है एमएमडीआर अधिनियम, क्योंकि स्पष्ट बहिष्करण पर विचार किया गया है संशोधित एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8A(9) के तहत।

निधि जैन

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।